Now, so far as the question of repetitive import of technology and other things is concerned, it is very difficult to go into a general question. If the hon. Member would put a specific question and say whether technology in this field which was available in this country has been imported. I would be able to give the reason why it has been imported. For instance, take torch cells and batteries. Now there are a number of companies which have been allowed to collaborate because their processes are different, and because of the different nature of processes, different needs are met. Now one can say, 'We should have only one collabaration in some torch cell.' and then some other hon. Member will say, 'You are building up monopoly. You should not allow only one company to collaborate as it will become a monopoly. Some other company must also get because if the technology is not available, they have also to get the collaboration.' Therefore, it is not a question where one can say, 'Yes' or 'No' in general terms. If there are specific problems, then I can discuss them.

MR. SPEAKER : Next question.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये सदन में थे। आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री मधु लिमये : मेरी बात सुन लीजिए ताकि आइन्दा सब लोगों का फायदा हो जाए। आपने यह प्रथा शुरू की है कि वहां पर सारे प्रश्नों के जवाब रखे जाते हैं, नोटिस आफिस में रखे जाते हैं —

MR. SPEAKER : That should be done earlier ; not during the Question Hour.

श्री मधु लिमये : उन्होंने कहा था कि आप वहां आइये। क्वेश्चन आवर शुरू होने के बाद वहां रखने का क्या मतलब है ?

श्री रवि राय : जवाब देखने के लिए गए थे।

MR. SPEAKER : Next question. I am sorry, I cannot allow this practice of going back. I have already taken up the Next question.

श्री मधु लिमये : कम से कम आदेश तो आप दें कि प्रश्नोत्तर शुरू होने के बाद प्रश्नों के जवाब यहां रखे जायें, नोटिस आफिस में रखकर क्या करेंगे ? मैं केवल जवाब देखने के लिए गया था, वर्ना मैं जाता ही नहीं। अगर आप अभी नहीं ले सकते हैं तो बारह बजे के बाद आप ले लीजिये।

MR. SPEAKER : If I finish the list and there is time left at the end I will see. Next question.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय अगर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

Declaring of Agricultural Industry as Major Industry

* 163. SHRI RAJDEO SINGH :
SHRI DEORAO PATIL :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether in view of the need and importance of farm production, Government are in a position to declare agricultural industry as a major industry ; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI DINESH SINGH) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Government has not evolved any scheme of classification by which a particular sector of economic activity can be declared as a major industry. The Industries (Development & Regulation) Act contains in its schedule only items involving manufacturing processes.

However, Government has consistently accorded the highest priority to the development of agriculture. The Fourth Five Year Plan envisages the following main elements in the strategy of agricultural production :—

(1) coordinated research in respect of all important crops ;

(2) continued expansion of irrigation facilities and reorientation of irrigation practices so as to ensure optimum and integrated use of ground and surface water ;

(3) improvement in the utilisation of existing irrigation potential through special programmes ;

(4) expansion in the supply of fertilisers, plant protection material, farm machinery and credit ;

(5) full exploitation of the possibilities of raising yields provided by the new seed varieties in the case of cereals ;

(6) intensive efforts in selected suitable areas for raising the yield levels of major commercial crops ;

(7) measures to increase intensity of cropping ; and

(8) improvement in the agricultural marketing system in the interests of the producer along with assurance of minimum prices for major agricultural commodities.

Based on this approach, a number of schemes will be implemented to step up agricultural production. These schemes include, inter alia, measures to step up the production of fertilisers, pesticides, tractors, agricultural implements etc. and encouragement to agro-based industries. The capacity of nitrogenous fertilisers will be increased from 1.02 million tonnes (in terms of 'N') in 1968-69 to 3 million tonnes in 1973-74. The capacity for agricultural tractors will be increased from 20,000 numbers in 1968-69 to 68,000 in 1973-74. In respect of agricultural implements, apart from the steps taken to increase their production, their distribution has been put on an organised basis by the establishment of agro-industries corporations which have been set up in 15 states as joint ventures of the Central and State Governments. Agro-based industries are being encouraged in the sector of village and small scale industries as well as in the cooperative sector.

A total outlay of Rs. 1328 crores, constituting 17.4% of the total plan outlay, is envisaged for the development of agriculture and allied sectors during the Fourth Plan period.

श्री देवराव पाटिल : उत्तर जो टेबल पर रखा गया है मुझे मिला नहीं है । मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उत्तर क्या है, इसको बता दें ताकि मैं पूरक प्रश्न पूछ सकूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर जरूर मिला होगा । कहीं भूल गए होंगे ।

श्री देवराव पाटिल : हम लोग गए थे हमको मिला नहीं । जो कुछ उत्तर है बता दें ।

MR. SPEAKER : As I could see, you have already got this copy. क्या मंत्री महोदय इसको पढ़ा सकेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : तीन पेज का है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा सुझाव है कि इसको स्थगित कर दिया जाए ताकि हम वक्तव्य पढ़ लें और उसके बाद सवाल कर सकें ।

श्री दिनेश सिंह : आप पहले वक्तव्य लेकर आए होते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वहां गए थे मिला नहीं । सबके लिए वक्तव्य नहीं रहता है, उधर वालों के लिए रहता है ।

श्री देवराव पाटिल : कापीज लिमिटेड रहती हैं । हम लेट गए थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो पहले जाते हैं उनको मिल जाता है, बाद वालों के लिए कापीज नहीं रहती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि हम जरा लेट गए थे । The Member should be vigilant about that.

श्री देवराव पाटिल : ग्यारह बजे से पहले गए थे ।

अध्यक्ष महोदय : लेट का मतलब क्या यह है कि बिस्तर पर लेट गए थे या वहां देरी से गए थे ।

SHRI K. NARAYANA RAO : The Member should be supplied the copy ; otherwise how can he put the supplementary questions ?

श्री देवराव पाटिल : कृषि भारत का महत्त्वपूर्ण उद्योग है । इसको उद्योग घोषित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह कहेंगे कि वक्तव्य पढ़ो ।

श्री दिनेश सिंह : जवाब तो माननीय सदस्य ने मेरी तरफ से दे दिया है । कृषि को उद्योग की किश्म से तो नहीं माना जाता है लेकिन कृषि की मदद के लिए एक काफी बड़ा मंत्रालय है और बड़े सुचारु रूप से वह कृषि की मदद करता है । उसका जो अपना ढंग है, जो उसके तरीके हैं, उसकी जो जरूरियात हैं उसको देखते हुए एक पूरा मंत्रालय स्थापित किया गया है जो देखता है कि किस तरह से हम कृषि की प्रगति में मदद कर सकते हैं । वह उद्योग नहीं है और न ही उसको हम उद्योग इस तरह से बना सकते हैं ।

श्री देवराव पाटिल : मंत्री महोदय कहते हैं कि कृषि उद्योग नहीं है । उसकी क्या वजह है ?

श्री रणधीर सिंह : अगर कृषि उद्योग नहीं है, तो वह क्या है ? क्या वह ड्रामा है ?

श्री दिनेश सिंह : वह कृषि है, उद्योग नहीं है । माननीय सदस्य कृषक हैं, उद्योगपति नहीं हैं ।

SHRI TENNETI VISWANATHAM : In the statement laid on the Table of the House, we find that :

> "Government have not evolved any scheme of classification by which a particular sector of economic activity can be declared as a major industry.".

After four Plans, is this the position to which Government has reduced itself ?

MR. SPEAKER : The hon. Member is asking for the hon. Minister's opinion. I do not think that he has asked any definite question. The hon. Minister need not answer this.

SHRI S.M. BANERJEE : In the statement, the hon. Minister has indicated a number of measures which are likely to be taken during the Fourth Plan in the strategy of agricultural production. The question put by my hon. friend Shri Deorao Patil was why this was not being treated as an industry. I would like to know from the hon. Minister whether the same protection will be given to the agricultural labour as is given to the industrial workers, and whether the same laws will be made applicable to them so that they are not exploited by the big farmers ?

SHRI DINESH SINGH : Certainly, it will be Government's constant endeavour to see that the agricultural worker is not exploited. In fact, certain arrangements have been made to try to give every encouragement in the agricultural field in this regard.

SHRI S.M. BANERJEE : My question was whether the same labour laws would be applied to them.

श्री विभूति मिश्र : गांधीजी ने भी कृषि को इण्डस्ट्री नहीं माना था। लेकिन उन्होंने यह माना था कि कृषि जीवन के लिए इतनी आवश्यक है कि अगर कृषि न रहे, तो आदमी मर जाये, जबकि अगर इण्डस्ट्री न रहे, तो आदमी मरेगा नहीं। कृषि के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के मंत्रालय से बहुत जरूरी काम पड़ता है, जैसे लोहा देना है। इसी प्रकार कृषि से जो पैदावार होती है, उसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का काम मंत्री महोदय के मंत्रालय का है। उस हद तक कृषि उद्योग के अन्तर्गत आता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मंत्रालय कृषि की कहां तक मदद करता है। अगर कृषि इस मंत्रालय में चला जाये, तो उससे इस मंत्रालय को क्या नुक्सान है? हिन्दुस्तान की पूरी राष्ट्रीय आय का 45 फीसदी कृषि से निकलता है और देश के 85 फीसदी लोग इससे जीवन-निर्वाह करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का मंत्रालय कृषि के बारे में क्या मदद करता है, कहां तक उसको सहयोग प्रदान करता है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है कि मुझे क्या एतराज है कि मैं कृषि को भी अपने मंत्रालय में ले लूं। मेरे साथी, माननीय कृषि मंत्री, बैठे हुए हैं। वह भी इस काम को देखने के लिए हैं। कोई कह सकता है कि उद्योग का काम भी वह ले लें। अलग-अलग मंत्रालय अलग-अलग कार्यों के लिए बने हुए हैं और उनके आपस में मिलकर एक अच्छा काम हो रहा है। जिस किसी को जो विशेष काम दिया गया है, वह उसको देख सकता है। जहां तक उद्योग मंत्रालय का सवाल है, कृषि में यंत्र आदि जिस सामान का इस्तेमाल होता है, उनके बनाने के लिए हमारे यहां से मदद दी जाती है। उसके बारे में हम कृषि मंत्रालय से बातचीत करके सब सम्भव सुविधा और सहायता दे सकते हैं और देते हैं। माननीय सदस्य ने लोहे और बिजली की बात कही है। उन दोनों से हमारे मंत्रालय का सम्बन्ध नहीं है। लेकिन लोहे और बिजली से मिलकर ट्रैक्टर और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आदि जो सामान बनता है, जिसकी देश में आवश्यकता है, उसके लिए हम सुविधा दे रहे हैं।

श्री महाराज सिंह भारती : देश में ट्रैक्टर सिर्फ बीस हजार बनते हैं, जब कि तीन लाख लोग वेटिंग लिस्ट पर हैं।

श्री दिनेश सिंह : अभी हमने बहुत नये ट्रैक्टरों के लिए लाइसेंसिज दिये हैं। हमें आशा है कि जल्दी और ट्रैक्टर उपलब्ध हो सकेंगे।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : In view of its great importance, if Government are not able to declare agriculture as an industry, will they at least transfer such industries as are connected with agriculture like the manufacture of tractors, tractor tyres, implements, fertilisers, etc. to the Agriculture Ministry ? We do not want any licence from Government to do agriculture. Even if they declare it as a major industry, we will not apply to them for grant of a licence for the purpose. So will they at least transfer these to the Agriculture Ministry in view of the bad experience the agriculturists are having ?

SHRI DINESH SINGH : The hon. member has already given one reason why we should not declare it an industry. He says then he will have to get an industrial licence. So far as tractor manufacture is concerned, it is already controlled by the Ministry of Agriculture. We work in very close co-operation. I cannot understand what he means by 'transferring' it to the Agriculture Ministry, whether he is thinking that Ministry start making tractors. The hon. Minister of Food and Agricuture is there. We can consider the suggestion.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : It is because the Industries Minister has become so inefficient that he cannot supply tractors and other things to agriculturists that we want it to be transferred to the Agriculture Ministry.

श्री रणधीर सिंह : मुझे मिनिस्टर साहब का यह जवाब सुनकर बेहद मायूसी हुई है कि एग्रीकल्चर एक इण्डस्ट्री नहीं है। इस देश में लक्सरीज तो इण्डस्ट्री मानी जाती हैं, लेकिन जराअत और खुराक को इण्डस्ट्री नहीं माना जा रहा है और न ही उसको इण्डस्ट्री की सहूलियात दी जा रही हैं। ऐसा करके एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। अगर मिनिस्टर साहब को एग्रीकल्चर को एक इण्डस्ट्री मानने से चिढ़ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इण्डस्ट्री को जो फैसिलिटीज, इनसेन्टिव्स और इमदाद दी जा रही है, क्या कम से कम वही सहूलियतें और इनसेन्टिव्ज एग्रीकल्चर को देने के बारे में मिनिस्टर साहब सोचेंगे? मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है, क्या वह उसको रिवाइज करने और एग्रीकल्चर को बिजली और इम्प्लीमेंट्स सप्लाई करने और किसानों को ठीक कीमत दिलाने के बारे में फिर से सोचेंगे, ताकि किसानों के साथ वही सलूक हो, जो कि इण्डस्ट्रीज के साथ ताल्लुक रखने वाले पांच फीसदी लोगों के साथ होता है?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बहुत भली-भांति कृषकों को सब प्रकार की सुविधायें देने के बारे में देख रही है। अगर माननीय सदस्य यह समझें कि उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने से कृषकों को ज्यादा फायदा होगा, तो मेरे ख्याल से यह उनकी गलतफहमी है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं।

SHRI RANGA : It should not be understood that all of us are in favour of this idea that agriculture should be classified as an industry. Far from it. Agriculturists would not like their occupation to be treated as an industry and then be brought under all the disabilities from which industries are made to suffer. At the same time, would the hon. Minister assure us that there is a co-ordinating committee between his Ministry and the Agriculture Ministry to ensure that adequate protection and assistance are being offered to agriculturists from the industry side in regard all those associated industries which are expected to cater to the needs of the agriculturists ?

SHRI DINESH SINGH : Yes. I assure the hon. Member that there is complete co-ordination between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Industry regarding the manufacture of implements and requirements.

SHRI RANGA : Is there any committee either at the secretarial or ministerial level ? If there is no such committee, will Government consider that suggestion ?

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मधु लिमये जी के क्वेश्चन को आप इजाजत देंगे ?

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय की अगर इनायत हो जाय तो मेरे सवाल को ले लीजिए।

MR. SPEAKER : Will think of some other way of bringing it. Do not try to introduce a practice which will be bad for the future. It is only for your own good.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Suggestions of N. C. A. E. R. Regarding Industrial Growth

*152. SHRI R. K. BIRLA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether at a Seminar organised by the National Council of Applied Economic Research in Delhi in September 1970, a suggestion was made for the removal of industrial bottlenecks in order to build up growth potential in the economy ;

(b) whether Government representatives also participated in the seminar and if so, the names of the representatives ;

(c) the details of the suggestions made in the seminar ; and

(d) the action being taken by Government to remove the bottlenecks ?